

(ब) उन आवास समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशों के अनुसार मूल्य वापस भुगतान नहीं किये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुक्तिकारण साहू) : (क) और (ख) . वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को मूल्य स्वीकृत नहीं किया है। किन्तु सूचना मिली है कि भारतीय स्टेट बैंक ने, इस बैंक के अपने कर्मचारियों द्वारा निर्मित सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों को 31 दिसम्बर, 1978 तक 1.61 करोड़ रुपये के मूल्य प्रदान किये थे। इन सोसाइटियों द्वारा मूल्य की अदायगी में कोई बाकीबारी नहीं है।

जुट गॉट संच द्वारा जूट का निर्यात

1720. श्री बहारलाल साहू : क्या बाणिज्य तथा नागरिक प्रगति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट उत्पादकों की सहायता करने की दृष्टि से जूट गॉट संच ने 2 लाख टन जूट का निर्यात करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

बाणिज्य, नागरिक प्रगति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भार्गव बेग) : (क) जी हाँ

(ख) कच्चे पटसन के निर्यात के लिए उचित मूल्य बाजार में सप्लाई तथा मांग सहित सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

फाउन्ड्री उपकरणों का निर्यात

1721. श्री दया राम शास्त्री : क्या बाणिज्य तथा नागरिक प्रगति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन शो काँ के दौरान प्रत्येक देश को कितने मूल्य के फाउन्ड्री उपकरणों का निर्यात किया गया और इससे परिणामस्वरूप सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय फाउन्ड्री के उपकरणों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ रही है और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

बाणिज्य, नागरिक प्रगति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भार्गव बेग) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हाँ। इकीनिवरी निर्यात संवर्धन परिषद् विदेशी खरीदारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये बाजार संभाव्यता और उत्पादन विकास का मूल्यांकन करने की दृष्टि से विदेशों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में यात्रा लेती है और अध्ययन दल प्रयोजित करती है। विदेशी खरीदारों को यह दिखाने के लिये कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये भारतीय उत्पादकों के पास कितनी क्षमता है, परिषद् ने उनके प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है।

विवरण

(क) उन प्रमुख देशों की सूची जिन्हें वे गैर निर्यात की गई तथा साथ ही उनके क्षेत्र नीचे दिये गए हैं।

(लाघ ६.० में)

वस्तु/देश	1976-77	1977-78
1. सी आई. मेलहोल कबल		
संयुक्त राज्य अमरीका	194.85	394.47
कनाडा	55.22	59.13
सऊदी अरब	69.84	115.68
जुबैत	43.15	84.07
संयुक्त अरब अमीरात	21.84	27.66
कीनिया	8.26	14.63
कतार	8.81	4.76
सिंगापुर	8.26	19.48
ओमान	5.23	0.74
तंजानिया	1.78	10.67
अन्य	9.66	44.04
योग	426.90	775.33

2. सी आई. पाइप तथा फिटिंग्स

इराक	70.95	9.92
मिस्र का अरब गणराज्य	55.02	62.35
हांगकांग	83.29	66.04
कीनिया	24.61	40.68
जुबैत	342.88	256.89
लीबिया	—	43.05
नेपाल	13.61	52.04
कतार	30.35	42.14
सऊदी अरब	228.38	466.41
तंजानिया	5.91	40.72

	1976-77	1977-78
संयुक्त राज्य अमेरिका	457.40	382.44
संयुक्त राज्य अमेरिका	53.60	59.06
सिन्हापुर	273.20	294.15
बहरीन	7.66	15.57
कनाडा	16.93	16.34
बंगला देश	5.85	18.18
इरान	3.01	26.85
सोमान	24.58	20.94
अन्य	161.17	138.38
योग	1858.49	1959.69

3. सी०आई० स्म पाथ 1976-77 के सी०आई० पाथ तथा फिटिंग के प्राकड़ों में शामिल हैं।

आस्ट्रेलिया	78.39
बर्मा	95.73
कुवैत	7.36
नलबेनिया	10.61
नाइजीरिया	15.52
सिन्हापुर	68.62
श्री लंका	13.19
तंजानिया	26.72
फिटेन	25.39
संयुक्त राज्य अमेरिका	13.71
सोमिया	237.97
अन्य	15.53
योग	547.84

4. इंडोनेशियन कार्टिंग

अमेरिका	9.63	24.10
कनाडा	10.42	12.07
कोरिया (उत्तरी)	—	19.82
कोरिया (दक्षिणी)	—	16.41
चीन	1.72	5.56
जपान	6.91	4.05

	1976-77	1977-78
फिटेन	9.20	3.49
बंगला देश	9.63	3.28
संयुक्त राज्य अमेरिका	72.00	104.83
यूगोस्लाविया	39.05	16.38
अन्य	23.68	36.68
योग	189.64	250.07

5. स्टील कार्टिंग

कुवैत	11.84	9.54
श्री लंका	5.89	1.71
स्वीडन	9.67	—
दक्षिणी कोरिया	—	43.33
मिस्र का अरब गणराज्य	—	8.39
आस्ट्रेलिया	3.17	3.50
बंगला देश	—	11.59
तंजानिया	—	4.20
संयुक्त राज्य अमेरिका	7.1	4.05
यूगोस्लाविया	9.98	2.70
अन्य	7.86	41.22
योग	54.62	121.22

Boosting of India's Export

1722. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether in order to boost export his Ministry has asked all State Government Trade Corporations to open the Branches in more places in their States recently;

(b) if so, response of the State Governments and Corporations therein; and

(c) progress achieved upto the end of January, 1979?